Memorandum of Understanding is concerned, I would like to say that it deals with the question of exploring the sea sand where several minerals are available. Previously, it was to be exported for the purpose of getting synthetic materials, but, now, this joint venture agreement explores the possibility of having the synthetic rutile in India itself. That is why we have entered into this particular joint venture.

MR. CHAIRMAN:Question No. 60.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I have to put my second supplementary. Please allow me.

MR. CHAIRMAN: Please cooperate with me. This is the last question.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: All right, Sir.

**Child Labour in Andhra Pradesh**

*60. SHRI RUMANDLA RAAMACHANDRAYYA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether there are over 1.5 lakh child labourers languishing in slavery in different parts of Kurnool district in Andhra Pradesh;

(b) if so, whether the district administration has set upon the task of identifying and rehabilitating child workers slogging in cement quarries, cotton grading units, etc;

(c) whether any raids were conducted;

(d) if so, the number of children captured during these raids; and

(e) what are the steps being taken by the Government to rehabilitate them?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SAHIB SINGH VERMA): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

***Statement***

(a) to (e) As per the information received from the State Government of Andhra Pradesh, there are no such instances. The district administration has been undertaking identification and rehabilitation of child labourers on a continuous basis. Special squads comprising of representatives from school education, labour, revneue and other departments carry out inspections/raids periodically to detect cases of child labour. During the

period from July 2002 upto 10.02.2003, 79 children in hazardous occupations and 535 children in non-hazardous occupations were detected. The child labourers identified during inspections/raids are being rehabilitated through various National Child Labour Project schools, residential bridge courses and alternative schools under District Primary Education Programme, gurukulams under Velugu Project and Social Welfare Hostels.

**12.00** NOON

**श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या:** सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि बाल श्रमिकों के बारे में मैंने प्रश्न किया है। आन्ध्र प्रदेश की पद्धति इन्होंने बताई है। सारे भारत में बाल श्रमिकों को दूर करने के लिए भारत सरकार के पास कोई ऐसी प्रणाली है जैसे नवोदय पाठशाला है? ऐसी कोई पाठशाला रखकर इन बाल श्रमिकों को वहां विद्या, भोजन आदि देने का प्रावधान कर रहे हैं?

**श्री साहिब सिंह वर्मा:** उत्तर में यह दिया गया है कि ऐसे सभी बच्चों को हम गुरुकुलों में भेजते हैं, आवासीय ब्रिज पाठ्यक्रम देते हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा दिलवाते हैं, वैकल्पिक स्कूल चलाते हैं और वेलुगू परियोजना के अंतर्गत इनको इस प्रकार की सारी सेवा सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। जहां तक सारे देश में इसको लागू करने का प्रश्न है, अभी हम पहले सौ जिलों में इसको चलाते थे। इस पंचवर्षीय योजना में पचास जिलों में और प्रारम्भ किया है। हमारी यह इच्छा है कि देश से बाल श्रमिक पूरी तरह से खत्म हों और एक कम्प्लेंट के रूप में हम इस पूरे कार्यक्रम को लेने वाले हैं।

**श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या:** इतना करने के बावजूद भी सारे भारत देश में करोड़ों बाल श्रमिक काम कर रहे हैं, उनको सुधारने के लिए विशेष लाभदायक होने के लिए, आपके पास इतने स्कूल रहने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। उन बच्चों को स्वतंत्रता मिलने के लिए भारत सरकार के पास क्या विशेष पैकेज प्रणाली है, कृपया बताएं?

**श्री साहिब सिंह वर्मा:** माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 1981 में एक करोड़ छत्तीस लाख बाल श्रमिक थे। 1991 में एक करोड़ बारह लाख के करीब हैं। एक और सर्वे के मुताबिक एक करोड़ चार लाख हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि कुछ फर्क नहीं पड़ा है। हां, मैं यह स्वीकार करता हूं कि जिस प्रकार से पड़ना चाहिए उस प्रकार से नहीं पड़ा है। इसकी जड़ में गरीबी है। जब तक देश से गरीबी नहीं मिटेगी तब तक न तो सब लोगों को शिक्षा दी जा सकती है और न ही बाल श्रम को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए अनेकों योजनाएं चलाई गई हैं। इन योजनाओं पर और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से काम करने की आवश्यकता है। इन योजनाओं को इंटिगरेट करने की आवश्यकता

है। अनेकों योजनाएं मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही हैं। अगर राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसे एक मूवमेंट के रूप में लेंगे, एक आंदोलन के रूप में लेंगे, सभी राज्य सरकारें काम करेंगी तो निश्चित रूप से हम इसे कर सकते हैं। वरना आपने जो कही वह बात सही है। जहां तक बाल श्रम की बात है तो जब तक देश से गरीबी खत्म नहीं होगी, तब तक यह खत्म नहीं होगा। गरीब को रोटी चाहिए इसके लिए वह अपने बच्चों को काम पर भेजता है। इसे खत्म करने के लिए सरकार की अनेकों योजनाएं हैं। जब ये योजनाएं फलीभूत होंगी तब निश्चित रूप से बाल श्रम खत्म होगा।

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Question Hour is over.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: I congratulate the hon. Chairman on completing all the questions.

---

## WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

### Buffer stock of sugar

*43. SHRI NANDYELLAIAH:
DR. T. SUBBARAMI REDDY:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that differences are getting sharper between sugar mills in the co-operative and private sectors over modalities for allocation of the recently announced buffer stock of 20 lakh tonne;

(b) if so, what are the main differences;

(c) whether Government have considered views of all the sugar mills; and

(d) if so, to what extent Government have compromised and satisfied the sugar mills for issue of buffer stock allocation?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD YADAV): (a) to (d) The suggestions received from the National Federation of Cooperative Sugar Factories (NFCSF) and the Indian Sugar Mills Association (ISMA) in respect of norms for allocation of buffer stock between the sugar factories were duly